बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 118

व्यापार समझौते अहम

इस बात को लेकर एक पारंपरिक समझ विकसित हुई है कि वैश्वीकरण की स्थिति पलट रही है और दुनिया व्यापार समझौतों और खुलेपन के विरुद्ध हो रही है। परंतु गत सप्ताह इस धारणा को तगड़ा झटका लगा। विश्व के सबसे बड़े कारोबारी संस्थानों में से एक यूरोपीय संघ ने दक्षिण अमेरिका के चार बड़े देशों-ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। ये चारों देश अभी हाल तक दुनिया के चौथे सबसे बड़े कारोबारी समूह मर्कोसर के बचे हुए पूर्णकालिक सदस्य थे। वेनेजुएला भी इसका सदस्य था लेकिन उसे दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक बार इन दोनों कारोबारी ब्लॉक के बीच व्यापार शुरू होने के बाद वे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएंगे। इस समझौते पर पहुंचने के लिए यूरोपीय संघ और मर्कोसर को 20 वर्ष लग गए। इस बीच दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ा। ब्राजील के नए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति को अतीत के जलवायु परिवर्तन समझौतों की अनदेखी संबंधी अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा ताकि यूरोपीय संघ से वार्ता जारी रह सके, उधर शक्तिशाली यूरोपीय कृषि लॉबी ने भी कुछ बलिदान किए। इससे अंदाजा लगता है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक और अफसरशाही जगत के नेता इस व्यापार समझौते से किस हद तक जुड़े हुए थे।

इसमें न केवल भारत बल्कि तमाम अन्य देशों के लिए भी कई अहम सबक छिपे हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान ब्रिटेन और अमेरिका को हुआ है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन बेल्जियम के साथ समझौता खत्म करेगा ताकि भविष्य में अपने लिए ऐसा कोई समझौता कर सके। यूरोपीय संघ और मर्कोसर समझौते की जटिलता ब्रिटेन के अक्खड़पन को उजागर करती है। उधर, डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका मुक्त व्यापार के लाभ को लेकर शंकालु ही नजर आया है। परंतु यूरोपीय संघ और मर्कोसर दोनों अमेरिका के बड़े कारोबारी सहयोगी हैं, इन दोनों ने इस समझौते से यह दिखाया है कि वे अमेरिका की दिखाई राह पर चलना नहीं चाहते।

परंतु जिन देशों को इससे सबक लेना चाहिए, उनमें भारत भी शामिल है क्योंकि वह भी नए व्यापार समझौतों को लेकर खासा अनिच्छुक नजर आया है। इस बीच उसके कई कारोबारी साझेदार अपने बाजार को मजबूत बनाने के नए तरीके तलाश रहे हैं। जबकि अन्य प्राथमिकता वाले कारोबारी मानक भारतीय निर्यातकों के लिए बंद हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक पहले ही बांग्लादेश जैसे शुल्क मुक्त पहुंच वाले देशों की तुलना में यूरोपीय देशों के लिए महंगे हो चुके हैं। अब मर्कोसर की ओर से एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। अमेरिका ने जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेंशियल स्कीम के तहत कई भारतीय उत्पादों को मिलने वाली शुल्क मुक्ति हाल ही में समाप्त की है। इससे भी मैक्सिको आदि देशों की तुलना में भारतीय निर्यातकों को नुकसान ही होगा। अब वक्त आ गया है कि भारत यूरोपीय संघ के साथ स्थगित पड़ी मुक्त व्यापार वार्ता को दोबारा शुरू करे।

यूरोपीय संघ ने कृषि से जुड़े मुद्दों पर समझौते की मंशा जताई है, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। भले ही डेरी, वाहन निर्माता और औषधि आदि शक्तिशाली समूह इससे नाखुश हों। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को भारत की सहभागिता के बिना आगे बढ़ने देने की कीमत हमें वैश्विक व्यापार मंच पर अलग-थलग पड़ने के रूप में चुकानी होगी। श्रम आधारित क्षेत्र मसलन चमड़ा और वस्त्र, जो रोजगार तैयार करने की दृष्टि से अहम हैं, उन्हें इसका खमियाजा उठाना होगा। भारत विकास की इस अवस्था में यूं अलग-थलग होना गवारा नहीं कर सकता।

अजय मोहंती

केंद्रीय बजट पर टिकीं बैंकिंग जगत की उम्मीदें

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण एक साहसिक विचार है और नोटबंदी जैसा कदम उठा चुकी सरकार के लिए यह काफी आसान हो सकता है। बता रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

आम बजट आने के ठीक पहले सभी उद्योग इकाइयां अपने एजेंडे के साथ नॉर्थ ब्लॉक पहुंचती हैं। बैंकिंग उद्योग के लिए यह सालाना परिपाटी म्युचुअल फंडों और सरकारी बचत योजनाओं की तुलना में असमान कारोबारी हालात का मुद्दा उठाता रहता है। बैंकों को यह उलझन सताती है कि अगर ब्याज दरों में कटौती की तो ग्राहक म्युचुअल फंडों और अधिक प्रतिफल देने वाली सरकारी बचत योजनाओं का रुख करने लगेंगे। बजट के ठीक पहले सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें कम कर दी हैं और बाजार नियामक की नई भूमिका के चलते कंपनियां अपने फंड म्युचुअल फंड से हटाकर बैंकों से संबद्ध करने के लिए बाध्य हो सकती हैं।

ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए? यहां पर कुछ सुझाव पेश हैं जो अनपेक्षित भी नहीं हैं क्योंकि खुद वित्त मंत्री ने ट्विटर पर सलाह मांगी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने वर्ष 2016 से उद्योग समूहों और अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की परंपरा जारी रखने के साथ ही बजट के बारे में आम जनता से भी राय लेने का सिलसिला शुरू किया है। भले ही मैं आधिकारिक समयसीमा में सलाह देने से चूक गया हूं लेकिन फिर भी मैं इस भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं।

कुछ समय तक सार्वजनिक बैंकों की जोखिम विमुखता कॉकटेल जगत में चर्चा का मुद्दा रही है। बैंकों की कर्ज देने की अनिच्छा उनकी चिंता रही है। दरअसल इस समस्या की जड़ में डर से जुड़ा मनोविकार है। जांच एजेंसियां वरिष्ठ बैंकरों का पीछा कर रही हैं और एक निजी बैंक के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) का मामला छोड़ दें तो वे सरकारी नियंत्रण वाले बैंकों के अधिकारियों के मामले में खासी आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। इनमें से कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई से पूछताछ हुई है लेकिन अब तक एक भी ऐसा वाकया नहीं आया है जब कर्ज देने या किसी चूककर्ता की बकाया राशि निपटाने जैसे फैसलों को लेकर किसी सार्वजनिक बैंकर के खिलाफ अभियोग चला हो। लेकिन बैंकरों का यह डर कर्ज आवंटन के साथ फंसे कर्ज की वसूली को भी धीमा कर रहा है। इस समय इन बैंकरों में भरोसा बहाल करना होगा जिनके पास कुल बैंकिंग उद्योग का करीब 70 फीसदी हिस्सा है। निश्चित रूप से दोषी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन महज आरोपों के आधार पर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए और न ही उनकी छवि धूमिल की जानी चाहिए।

वरिष्ठ बैंकरों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए लेकिन उन्हें समुचित ढंग से पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। हमें सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के वेतन ढांचे को नौकरशाहों के वेतन से अलग करके देखना चाहिए क्योंकि दोनों के काम का स्वरूप अलग है। प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। दो सार्वजनिक बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प देने का प्रस्ताव कई वर्षों से नॉर्थ ब्लॉक के भीतर धूल खा रहा है।

एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है और फंसे हुए कर्जों के बोझ तले दबे सार्वजनिक बैंक यह सार्थक भूमिका नहीं निभा सकते हैं। गैर-बैंकिंग वित्त क्षेत्र में पैदा हुए हालिया संकट ने इस समस्या को और भी गंभीर बनाया है और कई बैंकों पर नए सिरे से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। इस समस्या से निपटने का परंपरागत तरीका इन बैंकों में नई पूंजी डालने का रहा है। सरकार अब तक इन बैंकों में 3.5 लाख करोड़ रुपये डाल चुकी है जिसमें से करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये वर्ष 2009 के बाद आए हैं।

केंद्रीय बजट पर भरोसा

पिछले दो वर्षों में ही सरकार ने बीमार सार्वजनिक बैंकों को दुरुस्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये डाले हैं। रिकॉर्ड के तौर पर, वित्त वर्ष 2015-16 में रिजर्व बैंक के हाथों बैंकों के बैलेंसशीट की कथित परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शुरू होने के बाद से सार्वजनिक बैंकों का शुद्ध घाटा 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा है। राजग के पिछले वर्षों के शासन में सार्वजनिक बैंकों को तीन साल घाटा उठाना पड़ा और लाभ के दो वर्षों में भी केवल 35,000 करोड़ ही कमाए।

फंसे कर्जों के निपटान के लिए बैंकों की तरफ से किए गए 9.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान इस भारी घाटे की वजह रही है। सार्वजनिक बैंकों का सकल फंसा कर्ज 2014-15 में 2.62 लाख करोड़ रुपये था लेकिन अगले ही साल एक्यूआर लागू होने से यह उछलकर 5.16 लाख करोड़ और 2017-18 में 8.96 लाख करोड़ रुपये हो गया। वैसे 2018-19 में यह मामूली गिरावट के साथ 7.68 लाख करोड़ रुपये रहा? दो सार्वजनिक बैंकों का करीब एक-चौथाई कर्ज डूब रहा है। इसमें से एक बैंक का फंसा कर्ज कुल कर्ज का 20 फीसदी है तो दूसरे बैंक के लिए यह अनुपात 15 फीसदी है। ब्याज से होने वाली आय में बढ़त भी नहीं हो पा रही है क्योंकि की बैंक नए कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। जहां गत पांच वर्षों में बढ़े हुए वित्तीय प्रावधानों के चलते बैंकों का शुद्ध घाटा बढ़ा है लेकिन उनकी शुद्ध ब्याज आय भी 2014-15 के 1.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 2.3 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है।

सवाल उठता है कि सरकार को क्या इन बैंकों का स्वामित्व अपने पास बनाए रखना चाहिए? क्या इनका एकीकरण ही रामबाण इलाज है? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीमार चल रहे आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में सौंपने की बात कही थी और उसे अब पूरा भी किया जा चुका है। इस बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी सरकार के पास नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इसका नया मालिक बनकर सामने आया है। क्या यह निजीकरण है? देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के विलय के साथ बैंकों के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। बाद में सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में दो सार्वजनिक बैंकों का विलय कर अपनी मंशा साफ कर दी। क्या इससे भी समस्या का निदान होगा? क्या हमें इतने सारे सार्वजनिक बैंकों की जरूरत है? क्या उन सभी बैंकों का अलग समूहों में विलय कर बड़े बैंक बनाए जा सकते हैं?

एक पैनल ने सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाने का सुझाव दिया है जिसे सरकार अपनी हिस्सेदारी सौंप देगी ताकि कारगर ढंग से संचालन हो। हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह प्रस्ताव फिर से जिंदा हो चुका है। हो सकता है कि यह प्रस्ताव काम न करे क्योंकि सरकार के लिए अपना नियंत्रण छोड़ देना मुश्किल है। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करने का है जो सार्वजनिक बैंकों में न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास रहना अनिवार्य बनाता है।

कुछ कमजोर बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है लेकिन उनकी जवाबदेही भी काफी है। कुछ एनबीएफसी भी इसी तरह गहरे तरलता संकट के दौर से गुजर रही हैं जिससे उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कुछ कमजोर बैंकों को नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को क्यों न दे दिया जाए? हालांकि संभावित खरीदार के लिए बैंक संचालन संबंधी सभी शर्तें पूरी करनी जरूरी होंगी। सरकार कमजोर बैंकों की बिक्री से भी कमाई कर सकती है। ऐसा होने से सार्वजनिक बैंकों में पूंजी डालने का भी राजकोषीय घाटे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। यह एक साहसिक विचार है लेकिन नोटबंदी जैसा कदम उठा चुकी सरकार के लिए यह आसान हो सकता है।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

सीतारमण को अपने पहले बजट में साधने होंगे कई संतुलन

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को अपना पहला आम बजट पेश करेंगी तो आर्थिक वृद्धि बहाल करना, नए रोजगार पैदा करना, खर्चों में वृद्धि के जरिये अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना और राजकोषीय सुंतलन साधते हुए कर राहत देने के साथ ही बड़े सुधारों का एजेंडा रखना भी उनके सामने बड़े लक्ष्य होंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां भी होंगी जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ और आर्थिक दूरदर्शिता की भी परीक्षा लेंगे।

आम चुनाव और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पेश होने वाले बजट पर सबकी नजर रहती है। चुनाव के बाद पेश होने वाले आम बजट में पेश आंकड़ों की चुनाव से पहले रखे गए अंतरिम बजट से हमेशा ही तुलना की जाती है। वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गत 1 फरवरी को पेश किया था। महज पांच महीने बाद सीतारमण इस वित्त वर्ष का अंतिम बजट पेश करने वाली हैं। इस अल्प अवधि में ही अंतरिम बजट में 2018-19 के बारे में पेश किए गए आंकड़े काफी हद तक बदल चुके हैं। वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पेश किए जाते समय आंकड़ों में आए इस बदलाव का भी असर दिखेगा। सीतारमण इस चुनौती का सामना किस तरह करेंगी?

निश्चित रूप से, वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी बना रहा है। लेकिन अधिक परेशानी वाली बात यह है कि शुद्ध कर राजस्व संशोधित अनुमान से करीब 11 फीसदी तक कम हो गया है। संशोधित अनुमान में 14.84 लाख करोड़ रुपये रहा शुद्ध कर राजस्व 13.17 लाख करोड़ रुपये रहा। इसी तरह वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय का अनंतिम आंकड़ा संशोधित अनुमान से 1.32 लाख करोड़ रुपये कम हो गया है। यह व्यय बोझ सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के खातों पर डालने से यह कटौटी हासिल की जा सकी है लेकिन इसकी वजह से पीएसयू की उधारियां बढ़ गई हैं।

बजट से इतर की इतनी बड़ी उधारियों के चलते गैर-कर राजस्वों में मामूली बढ़त हुई है, पूंजीगत व्यय में दबाव और जीडीपी के आकार में मामूली वृद्धि होने से राजकोषीय घाटा 3.4 फीसदी के संशोधित अनुमान आंकड़ों के भीतर ही बना रहा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का शुद्ध कर राजस्व संशोधित अनुमान की तुलना में 11 फीसदी कम क्यों हो गया है और सरकार को अपना खर्च कम करने के लिए गैर-बजट उधारियों का सहारा क्यों लेना पड़ा?

इससे भी बड़ा सवाल और चुनौती यह होगी कि सीतारमण इस बड़ी राजस्व फिसलन और गैर-बजट उधारियों की व्याख्या अपने भाषण में किस तरह करेंगी? राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए यह एक असहज करने वाला पल होगा। मोदी सरकार की नई वित्त मंत्री को यह बताना होगा कि पिछली मोदी सरकार के ही एक वित्त मंत्री के अंतरिम बजट में किए गए संशोधित अनुमानों में क्या गड़बड़ी हो गई? जब अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट 10 जुलाई 2014 को पेश किया था तो उनके सामने यह विकल्प था कि पिछली सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 2014 के आम चुनाव के पहले पेश अंतरिम बजट के आंकड़ों से खुद को अलग कर लें। लेकिन जेटली उन आंकड़ों पर टिके रहे, हालांकि उनके पास इससे खुद को अलग करने का आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्पष्टीकरण था।

लेकिन सीतारमण के पास अपने पार्टी सहयोगी गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट के आंकड़ों से खुद को अलग करने की सियासी छूट नहीं है। फिर भी पिछले पांच महीनों में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और कर संग्रह के मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन को देखते हुए वित्त मंत्री के समक्ष इन आंकड़ों को सुधारने की आर्थिक जरूरत है। यही उनकी पहली चुनौती है।

सीतारमण की दूसरी चुनौती इस तथ्य से जुड़ी है कि उनका बजट इस वित्त वर्ष की बाकी बची तीन तिमाहियों के लिए लागू होगा। वित्त वर्ष की पहली तिमाही अवधि तो बीत चुकी है और इस अवधि के आंकड़े सरकारी राजस्व या उसके सब्सिडी भुगतान के बारे में बहुत अच्छी तस्वीर नहीं पेश करते हैं।

अंतरिम बजट के मुताबिक वर्ष 2019-20 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 7.61 लाख करोड़ रुपये रहेगा जिसमें केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल हैं। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही के दौरान संकलित जीएसटी राजस्व वार्षिक लक्ष्य का महज 19 फीसदी ही है और वह भी एकीकृत जीएसटी में 40 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के बाद। अप्रैल और मई में कंपनी कर संग्रह में 51 फीसदी की भारी गिरावट रही लेकिन जून के महीने में अग्रिम कर संग्रह की हालत में सुधार देखने को मिला है। इन दो महीनों में आयकर संग्रह 15 फीसदी बढ़ा है लेकिन इससे खास राहत नहीं मिलती है क्योंकि अंतरिम बजट में 2018-19 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 32 फीसदी बढ़ोतरी का जिक्र किया गया था। केवल सीमा शुल्क राजस्व में ही अनवरत वृद्धि का सिलसिला देखा गया है। अप्रैल-मई 2019 में यह 21 फीसदी बढ़ा है जबकि वार्षिक वृद्धि लक्ष्य 12 फीसदी का है। पेट्रोलियम एवं उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के मोर्चे पर इस पूरे वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट के एक-तिहाई से भी अधिक आवंटन इन दो महीनों में ही किया गया है।

संक्षेप में, सीतारमण की दूसरी चुनौती कहीं अधिक गंभीर नजर आती है। उन्हें अंतरिम बजट में राजस्व और सब्सिडी भुगतान को लेकर पेश आंकड़ों पर अधिक बारीक नजर रखनी है। अगर उन आंकड़ों को संशोधित किया जाता है और जमीनी हकीकत के करीब लाने के लिए उन्हें थोड़ा कम किया जाता है तो इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.4 फीसदी पर रखने का लक्ष्य इसकी भेंट चढ़ सकता है। शुक्रवार को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सीतारमण इस रस्सी पर चल पाने में किस कदर कामयाब रही हैं?

कानाफूसी

राज्य सभा में सौहार्द की मिसाल

गत मंगलवार को राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच सौहार्द का एक दृश्य देखने को मिला। दरअसल मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य विजय साई रेड्डी को मॉनसून सत्र के दौरान विशेष उल्लेख प्रस्तुत करना था। परंतु वह अपना चश्मा घर पर भूल आए थे। उन्होंने सदन को बताया कि वह ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका चश्मा घर पर छूट गया है। उनका इतना कहना था कि समाजवादी पार्टी के नेता नीरज शेखर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें अपना-अपना चश्मा देने की पेशकश की। बाद में रेड्डी ने पटेल के चश्मे की सहायता से काम पूरा किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी में संसद का यह पहला सत्र जून माह से आरंभ हुआ है।

टाइम मैगजीन और मंत्री

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में उद्योग भवन स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से मुलाकात की। उनके चैंबर में पहुंचने के बाद पत्रकारों ने देखा कि कॉफी टेबल पर टाइम मैगजीन का वह संस्करण रखा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को 'इंडियाज डिवाइडर इन चीफ' कहकर संबोधित किया गया था। हालांकि इसी अंक में उनको सुधारक बताता हुआ एक लेख भी था लेकिन उसका शीर्षक छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही पत्रकारों ने वहां चित्र लेने शुरू किए, पत्रिका वहां से हटा दी गई।

आपका पक्ष

चंद्रयान-2 मिशन की तैयारी पूरी

चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के 15 जुलाई को होने वाले प्रक्षेपण की तैयारी पूरी हो गई है। यह जानकारी संसद में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान दी। भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रयान-1 के तहत चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज की। इस बार का चंद्रयान-2 का मकसद चांद पर मानव जीवन की संभावना की खोज करना है। चंद्रयान-2 उपग्रह को जीएसएलवी-3 नामक रॉकेट ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के शिवन ने प्रक्षेपण की तारीख के बारे में पिछले महीने घोषणा की थी। उनके मुताबिक यह यान 6 या 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके साथ ऑर्बिटर में 8 पेलोड, 3 लैंडर और 2 रोवर होंगे। चांद के इस हिस्से के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और चंद्रयान-2 के कारण इस हिस्से के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यह वाक्य इसरो का आदर्श वाक्य है। इस सिद्धांत पर इसरो काम भी कर रहा है। संगठन से जुड़े तमाम वैज्ञानिक और कर्मचारी समर्पित भाव रखते हुए अथक परिश्रम के बल पर देश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं और प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का लोहा दुनिया में मनवा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हर महीने विभिन्न उपग्रह प्रक्षेपण के दम पर सुर्खियों में रहता है जिसमें अनेक उपग्रह प्रक्षेपणों में से वर्ष 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करना हर भारतीय के लिए गौरवशाली और यादगार क्षण था। वहीं मंगल ग्रह में उपग्रह भेजना भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए यादगार घटना रही क्योंकि मंगलयान की सफलता के साथ ही भारत पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसके अलावा आज से 10 साल पहले चंद्रयान-1 मिशन भी किया जा चुका है। वहीं चंद्रयान-2 अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान का उन्नत संस्करण है। संगठन के वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चंद्रयान-2 मिशन भी कामयाब होगा और इसके कामयाब होने पर चंद्रयान-2 मिशन इतिहास के पन्नों पर स्वयं सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

चंद्रमा में खोज के लिए चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई को किया जाएगा

समुचित जल प्रबंधन है समाधान

सरकार को जलसंकट से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक सहित सभी उपायों को अपनाना होगा। सांसदों को पानी की उपलब्धता बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं को सांसद निधि से बढ़ावा देने की जरूरत है। पानी के विषय पर समग्रता से व्यापक नीति बना कर उसे लागू किया जाए। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर को पेयजल पहुंचाने का है। देश में पेयजल कम नहीं हुआ, सिर्फ उचित जल प्रबंधन के अभाव और आबादी के बढ़ते बोझ ने इसे गंभीर चुनौती बना दिया है। हर साल भारत को 4,000 बीसीएम पानी वर्षा से मिलता है। इसमें से 1,137 बीसीएम पानी का ही उपयोग हो पाता है। पानी की उपलब्धता और उपभोग के बीच असंतुलन को समुचित जल प्रबंधन की मदद से दूर किया जा सकता है। देश में जल संरक्षण के साथ जल मितव्यता को रोकने की आवश्यकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।